

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3264
20 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

लाइट हाउस परियोजनाओं के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियां

3264. श्री पी. सी. मोहन:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किफायती आवास हेतु नवीन और टिकाऊ निर्माण प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर लाइट हाउस परियोजना (एलएचपी) पहल के अंतर्गत कितनी प्रगति हुई है तथा अब तक कितनी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं;

(ख) क्या कर्नाटक को उक्त पहल के अंतर्गत किसी लाइट हाउस परियोजना के लिए चुना गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) शहरी आवास आवश्यकताओं के लिए बेंगलुरु में नई निर्माण प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं; और

(घ) देश भर में एलएचपी के अंतर्गत शुरू की गई उन्नत प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं तथा कर्नाटक में शहरी वास्तुकारों और बिल्डरों के बीच क्षमता और जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या पहल की गई है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत, पहाड़ी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) सहित पूरे देश में आवासों के तेज, लागत प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिए निर्माण क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों द्वारा नवीन, स्थायी, पर्यावरण अनुकूल और आपदा-रोधी प्रौद्योगिकियों और निर्माण सामग्री को बढ़ावा देने और अपनाने के लिए एक प्रौद्योगिकी उप-मिशन (टीएसएम) की स्थापना की गई है।

वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती - भारत (जीएचटीसी-भारत) की शुरुआत वैश्विक स्तर पर उपलब्ध सर्वोत्तम सिद्ध निर्माण प्रौद्योगिकियों की पहचान करने और उन्हें मुख्य रूप से अपनाने के लिए की गई थी, जिसमें प्रीफैब्रिकेटेड प्रौद्योगिकी भी शामिल है, जो तेज, स्थायी, हरित और आपदा-रोधी हैं। जीएचटीसी-भारत के अंतर्गत, दुनिया भर से 54 नवीन सिद्ध निर्माण प्रौद्योगिकियों को चुना गया।

जीएचटीसी-इंडिया के तहत पहचानी गई 54 प्रौद्योगिकियों में से, छह लाइट हाउस परियोजनाएं (एलएचपी) हैं जिनमें 1,000 से अधिक आवास हैं, जिनमें छह अलग-अलग प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके संबद्ध इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं हैं, इनका निर्माण इंदौर (मध्य प्रदेश), राजकोट (गुजरात), चेन्नई (तमिलनाडु), रांची (झारखंड), अगरतला (त्रिपुरा) और लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में किया गया है। देश में भविष्य में मुख्य रूप से अपनाने के लिए इन प्रौद्योगिकियों के उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए चुनौती प्रक्रिया के माध्यम से एलएचपी के स्थलों का चयन किया गया था। चेन्नई, राजकोट, इंदौर, लखनऊ और रांची में एलएचपी का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और माननीय प्रधान मंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अगरतला में एलएचपी निर्माण के उन्नत चरण में है। कर्नाटक को उक्त पहल के तहत किसी भी लाइट हाउस परियोजना के लिए नहीं चुना गया है।

ये एलएचपी शहरी योजनाकारों, बिल्डरों और अन्य हितधारकों के बीच नवीन निर्माण प्रौद्योगिकियों/प्रणालियों के उपयोग और भारतीय संदर्भ में इन्हें मुख्य रूप से अपनाने के बारे में प्राप्त व्यापक सीख को बढ़ावा देने के लिए लाइव प्रयोगशालाओं के रूप में चालू हैं।

इसके अलावा, शहरी योजनाकारों, बिल्डरों, तकनीकी संस्थानों के संकाय/छात्रों, निजी/सार्वजनिक क्षेत्रों के तकनीकी व्यवसायियों, केंद्रीय/राज्य/शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) के अधिकारियों, स्टार्ट-अप/नवप्रवर्तकों/उद्यमियों और कर्नाटक सहित देश भर के अन्य संबंधित हितधारकों के बीच आवासों के तेज और गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिए क्षमता निर्माण और जागरूकता हेतु आधुनिक, अभिनव और हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए टीएसएम के तहत निम्नलिखित गतिविधियां शुरू की गई हैं जो शहरी आवास की जरूरतों को पूरा करें:

- i. सार्वजनिक/निजी एजेंसियों द्वारा अपनाने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों की पहचान, मूल्यांकन और प्रमाणन।
- ii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अभिनव और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और ऊर्जा कुशल सामग्री का प्रदर्शन करने और व्यवसायियों के बीच तकनीकी जागरूकता फैलाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके 13 प्रदर्शन आवास परियोजनाएं (डीएचपी) बनाई गई हैं।
- iii. निर्माण के लिए नई और उभरती हुई निर्माण सामग्री, प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं के बारे में भवन व्यवसायियों की क्षमता बढ़ाने के लिए नवरीतिह (भारतीय आवास के लिए नई, किफायती, मान्य, अनुसंधान नवाचार प्रौद्योगिकियां) नामक एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किया गया है।
- iv. वर्ष 2021 में भारतीय आवास प्रौद्योगिकी मेले (आईएचटीएम) का आयोजन घरेलू स्वदेशी और नवीन प्रौद्योगिकियों, निर्माण सामग्री और कम व मध्यम ऊंचाई वाले घरों की निर्माण प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने के लिए किया गया था। आईएचटीएम के तहत 84 नवीन प्रौद्योगिकियों/उत्पादों/सामग्रियों का चयन किया गया था। इसके अलावा, भारतीय शहरी

आवास कॉन्क्लेव 2022 के तहत 85 से अधिक नवीन निर्माण प्रणालियों और सामग्रियों को प्रदर्शित करने के लिए नवीन निर्माण प्रथाओं पर एक राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था।

v. जीआईजेड और निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी) के सहयोग से आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने रचना (रिजिलेंट, अफोर्डेबल एंड कमफर्टेबल हाउसिंग थ्रू नेशनल एक्शन) नाम से किफायती आवास के लिए नवीन निर्माण प्रौद्योगिकियों और थर्मल कम्फर्ट पर प्रशिक्षण/कार्यशालाओं की श्रृंखला आयोजित की। देश भर में 150 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं, जिनमें 11,000 से अधिक हितधारकों को शामिल किया गया है।

vi. उभरती प्रौद्योगिकियों की पहचान, मूल्यांकन और प्रमाणन के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन प्रमाणन योजना (पीएसीएस) संचालित की जा रही है जो देश की उन विभिन्न भू-जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल हैं, जो सुरक्षित, स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल हैं और बीएमटीपीसी द्वारा गुणवत्ता वाले आवासों की तेज प्रदायगी सुनिश्चित करते हैं। पीएसीएस के तहत, अब तक 77 नवीन उत्पादों और प्रणालियों को प्रमाणित किया गया है।

vii. नवीन निर्माण प्रौद्योगिकियों पर क्षमता निर्माण और हर संभव सहायता के लिए राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से ऑफसाइट कार्यशालाओं/वेबिनार, वेबकास्टिंग, तकनीकी जानकारी/मॉड्यूल पर परामर्श की एक श्रृंखला आयोजित की गई थी।

viii. नवीन निर्माण प्रौद्योगिकियों और तेज, पर्यावरण अनुकूल, ऊर्जा कुशल, लागत प्रभावी, पर्यावरण अनुकूल, आपदा प्रतिरोधी, स्थायी निर्माण प्रणालियों से संबंधित अन्य क्षेत्रों पर विभिन्न प्रकाशन किए गए हैं।

इसके अलावा, पीएमएवाई-यू के 9 वर्षों के कार्यान्वयन के अनुभवों से सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और कर्नाटक सहित देश भर के शहरी क्षेत्रों में एक करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों के लिए कार्यान्वयन हेतु 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है।

नवीन निर्माण प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए, पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत एक प्रौद्योगिकी और नवाचार उप-मिशन (टीआईएसएम) की स्थापना की गई है, ताकि नवीन डिजाइन और निर्माण प्रथाओं के लिए सहायता दी जा सके और शहरी योजनाकारों और बिल्डरों की क्षमता और जागरूकता बढ़ाई जा सके। टीआईएसएम पारंपरिक रूप से प्रचलित निर्माण सामग्री के स्थान पर आधुनिक निर्माण प्रौद्योगिकियों और सामग्री को मुख्य रूप से अपनाने और बढ़ाने के लिए विभिन्न नियामक और प्रशासनिक निकायों के साथ समन्वय के माध्यम से विभिन्न भू-जलवायु क्षेत्रों के लिए उपयुक्त लेआउट डिजाइन और भवन योजनाओं को अपनाने को बढ़ावा देता है।
